



इंटरनेट शटडाउन का प्रभाव

प्रलिस के लयः

संयुक्त राष्ट्र मानवाधकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR), #KEEPITON गठबंधन, वशिव बैंक ।

मेन्स के लयः

इंटरनेट शटडाउन और उसके नहतारथ ।

चरचा में क्यौं?

हाल ही में, [संयुक्त राष्ट्र मानवाधकार उच्चायुक्त कार्यालय \(OHCHR\)](#) द्वारा इंटरनेट शटडाउन नामक एक रपौरट प्रकाशति की गईः जसमें इसके रुझान, कारण, कानूनी नहतारथ और मानवाधकारों पर प्रभाव, वर्णति हैं तथा कहा गया है क इंटरनेट बंद करने से लोगों की सुरक्षा और कल्याण प्रभावति होता है, सूचना प्रवाह में बाधा आती है और अर्थव्यवस्था को क्षति पहुँचती है ।

इंटरनेट शटडाउनः

परचियः

- इंटरनेट शटडाउन के उपाय का उपयोग आमतौर पर तब कया जाता है जब नागरकि अशांति की स्थति होती है, ताक सिरकारी कार्रवाइयों के संबंध में सूचनाओं के प्रवाह को अवरुद्ध कया जा सके ।
- शटडाउन में अक्सर इंटरनेट कनेक्टविटी या प्रभावति सेवाओं की पहुँच को पूर्णतः प्रतबिंधति कया जाता है । हालाँक सिरकारें तेज़ी से बैडवडिथ को कम करने या मोबाइल सेवा को 2G तक सीमित करने का सहारा लेती हैं, जो नाममात्र की पहुँच बनाए रखते हुए इंटरनेट का सार्थक उपयोग करना बेहद मुश्कलि बना देती है ।
- दुनिया भर की सरकारों ने कई कारणों का हवाला देते हुए इंटरनेट को बंद करने का सहारा लया है
- इसके अलावा वीडियो, लाइव प्रसारण और अन्य पत्रकारति कार्यों को साझा करना तथा देखना मुश्कलि हो जाता है, जनिहें अक्सर नागरकि समाज आंदोलनों, सुरक्षा उपायों के साथ-साथ चुनावी कार्यवाही के दौरान आदेश दया जाता है और मानवाधकारों की नगिरानी व रपौरटिंग को गंभीर रूप से प्रतबिंधति करता है ।

संबंधति अंतरराष्ट्रीय ढाँचेः

- इंटरनेट शटडाउन कई मानवाधकारों को गंभीर रूप से प्रभावति करता है, साथ ही यह अभवियकृता की स्वतंत्रता और सुरक्षा तथा लोकतांत्रकि समाजों की नीव में से एक व्यकृता के पूर्ण वकिस के लयि अनवार्य शरत की जानकारी तक पहुँच को त्वरति रूप से प्रभावति करता है ।
- यह नागरकि और राजनीतिक अधकारों और अन्य मानवाधकार उपकरणों (अर्थात् [मानवाधकारों की सार्वभौमकि घोषणा](#)) पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध में गारंटीकृत अन्य सभी अधकारों के लयि एक मानदंड है ।
- [सतत वकिस लक्ष्य](#) अन्यायपूर्ण प्रतबिंधों से मुक्त, सार्वभौमकि रूप से उपलब्ध और सुलभ इंटरनेट द्वारा कार्य करने के लयि राज्यों के मानवाधकार दायतिवों को सुदृढ करते हैं ।
- संचार नेटवर्क में अंतरराष्ट्रीय कनेक्टविटी की सुवधा के लयि स्थापति, [अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ](#) (ITU) मानकों को अपनाने पर कार्य करता है जो सुनिश्चति करता है क नेटवर्क और प्रौद्योगकियि आपस में जुड़ती हैं तथा इंटरनेट तक पहुँच में सुधार करने का प्रयास करती हैं ।

प्रमुख नषिकरषः

वैश्वकि परदृश्यः

- दुनिया का ध्यान खींचने वाला पहला बड़ा इंटरनेट शटडाउन वर्ष 2011 में मसिर में हुआ था और इसके साथ ही सैकड़ों गरिफ्तारयि और हत्याएँ भी हुई थी ।
- [#कीपइऑन गठबंधन \(#KeepItOn coalition\)](#), जो दुनिया भर में इंटरनेट शटडाउन एपसोड की नगिरानी करता है, द्वारा वर्ष

2016-2021 तक 74 देशों में 931 शटडाउन का दस्तावेजीकरण किया गया।

- उस अवधि के दौरान 12 देशों द्वारा 10 से अधिक शटडाउन लागू किये गए। वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रों में कई शटडाउन का सामना किया गया है, लेकिन अधिकांश रपिर्ट एशिया और अफ्रीका में हुई है।
- नागरिक समाज समूहों द्वारा दर्ज किये गए शटडाउन में से 132 को आधिकारिक तौर पर अभद्र भाषा, दुष्प्रचार या अवैध या हानिकारक समझी जाने वाली सामग्री के अन्य रूपों के प्रसार को नयितरति करने की आवश्यकता द्वारा उचित ठहराया गया था।

■ भारतीय परिदृश्य:

- भारत ने इंटरनेट कनेक्शन को 106 बार अवरुद्ध या बाधित किया तथा भारत के कम-से-कम 85 इंटरनेट शटडाउन एपिसोड जम्मू और कश्मीर में हुए।
- नागरिक समाज समूहों द्वारा वर्ष 2016-2021 तक दर्ज किये गए सभी शटडाउन में से लगभग आधे को वरिध और राजनीतिक संकटों के संदर्भ में किया गया था, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक शकियतों की एक वरिध शृंखला से संबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान 225 शटडाउन दर्ज किये गए थे।

■ चुनाव के दौरान शटडाउन:

- यह डिजिटल उपकरणों तक पहुँच को समाप्त करता है जो चुनाव प्रचार, सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा देने, मतदान करने और चुनावी प्रक्रियाओं की देख-रेख के लिये महत्वपूर्ण हैं।
- अकेले वर्ष 2019 में 14 अफ्रीकी देशों ने चुनावी अवधि के दौरान इंटरनेट तक पहुँच को बाधित कर दिया।
- ये व्यवधान नषिकष पत्रकारों और मीडिया के काम को सामान्य रूप से बाधित करते हैं। युगांडा में शटडाउन ने हसिक दमनकारी उपायों की रपिर्टों के बीच वर्ष 2021 में चुनावों के मीडिया कवरेज को कमजोर कर दिया।
- चुनावी अवधि के दौरान वरिध के बाद शटडाउन बेलारूस और नाइजर जैसे देशों में भी रपिर्ट किये गए थे।

■ इंटरनेट शटडाउन का प्रभाव:

- **आर्थिक गतिविधियों पर:** यह सभी क्षेत्रों के लिये बड़ी आर्थिक लागत का कारण बनता है, वरिध लेनदेन, वाणज्य और उद्योग को बाधित करता है।
 - **वशिव बैंक** ने हाल ही में गणना की है कि अकेले म्यांमार में इंटरनेट शटडाउन की लागत फरवरी-दसंबर 2021 से लगभग 2.8 बलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो पछिले दशक में हुई आर्थिक प्रगत को उलट देती है।
- **शकषा पर:** यह सीखने के परणामों को कमजोर करता है और शकषकों, स्कूल प्रशासकों, परवारों के बीच शकषा योजना एवं संचार में हस्तक्षेप करता है।
- **स्वास्थ्य और मानवीय सहायता तक पहुँच पर:**
 - अध्ययनों ने स्वास्थ्य प्रणालियों पर शटडाउन के महत्वपूर्ण प्रभावों को दिखाया है, जिसमें तत्काल चकितिसा देखभाल जुटाना, आवश्यक दवाओं की डलिवरी और उपकरणों के रखरखाव में बाधा डालना, चकितिसा कर्मियों के बीच स्वास्थ्य सूचनाओं के आदान-प्रदान को सीमित करना और आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य सहायता को बाधित करना शामिल है।
 - सहायता प्रदान करने के लिये मानवीय अभकिरत्ताओं की कषमता पर इंटरनेट शटडाउन का गहरा प्रभाव पड़ता है। आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं के वरिध के लिये महत्वपूर्ण सूचना के प्रवाह को बाधित किया जा सकता है।
 - म्यांमार में इंटरनेट शटडाउन ने कथित तौर पर स्थानीय सहायता संगठनों को संकट में डाल दिया, क्योंकि इसने उन्हें धन मांगने और प्राप्त करने से रोका था।

इंटरनेट शटडाउन हेतु भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दशान-नरिदेश:

- जैसा कि अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया कि इंटरनेट शटडाउन भारतीय संवधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं करता है। यह एक उचित प्रतबिध के रूप में कार्य करता है और इसे केवल तभी अधनियमति किया जाना चाहिये जब सार्वजनिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये कोई वास्तविक खतरा हो। कुछ संतुलन परीक्षण किये जाने चाहिये तथा केवल अत्यधिक आवश्यक होने पर ही सरकार को इस अत्यंत प्रतबिधात्मक कदम का प्रयोग करना चाहिये।

आगे की राह

- रपिर्ट में कहा गया है कि इंटरनेट शटडाउन की अधिक आवृत्ति की प्रवृत्ति को रोकने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक उपायों और उनके प्रभावों की सीमित दृश्यता है।
- रपिर्ट में राज्यों से शटडाउन से परहेज करने, इंटरनेट पहुँच को अधिकतम करने और संचार के रास्ते में कई बाधाओं को दूर करने का आग्रह किया गया है।
- इसने कंपनियों से व्यवधानों पर सूचनाओं को तेजी से साझा करने और यह सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया कि वे शटडाउन को रोकने के लिये सभी संभव कानूनी उपाय करें जिन्हें उन्हें लागू करने के लिये कहा गया है।
- शटडाउन डिजिटल डिविड को कम करने के प्रयासों, त्वरित आर्थिक और सामाजिक विकास के वादे को कमजोर करते हैं, जिससे सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि को खतरा होगा।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

